

रंगनाथ रपिोर्ट और धर्मांतरति दलतियों के लयि आरकषण

प्रलिमिंस के लयि:

[अनुसूचति जातकी मानयता हेतु मानदंड](#), 1950 का संवधान (अनुसूचति जात) आदेश, भारत का महारजसिटरार

मेन्स के लयि:

अनुसूचति जातके दरजे के लए मानदंड और दलति ईसाइयों एवं मुसलमानों को शामिल करने के पक्ष व वपिकष में तरक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने धार्मकि और भाषायी अल्पसंख्यकों के लयि न्यायमूर्ति रंगनाथ मशि्रा आयोग की वर्ष 2007 की एक रपिोर्ट का पुनः अवलोकन कयि, जसिमें ईसाई और इस्लाम में परविरतति दलतियों के लयि [अनुसूचति जात \(SC\) आरकषण](#) की सफिरशि की गई थी ।

- केंद्र ने इस रपिोर्ट को खारज़ि कर दयि था , लेकिन शीर्ष न्यायालय का मानना है कि इसमें मौजूद जानकारयिों महत्त्वपूर्ण हैं जनिका उपयोग यह नरिधारति करने में मदद कर सकता है कि वर्ष 1950 के संवधान आदेश के अनुसार अनुसूचति जात वरग से धर्मांतरति दलतियों को बाहर करना असंवैधानकि है अथवा नहीं ।

नोट:

- मशि्रा रपिोर्ट को खारज़ि करते हुए सरकार ने हाल ही में एक पूर्व न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में नया आयोग गठति कयि था । सरकार ने "ऐतहासकि रूप से अनुसूचति जातयिों से संबंध रखने वाले परंतु हदि, बौद्ध और सखि धर्म के अतरिकित अन्य धर्मों में परविरतति होने वाले" लोगों को अनुसूचति जात का दरजा देने के सवाल पर एक रपिोर्ट तैयार करने के लयि दो वर्ष का समय दयि ।
- इस रपिोर्ट को खारज़ि करने के पीछे केंद्र का तरक है कि "ऐसे दलति जो जात के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लयि ईसाई अथवा इस्लाम में परविरतति हो गए हैं, वे उन लोगों द्वारा प्राप्त आरकषण लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने हदि धार्मकि व्यवस्था में बने रहने का वकिल्प चुना है ।"

रंगनाथ रपिोर्ट के मुख्य बदि:

- धार्मकि और भाषायी अल्पसंख्यकों के लयि न्यायमूर्ति रंगनाथ मशि्रा आयोग की वर्ष 2007 की रपिोर्ट में ईसाई तथा इस्लाम धर्म में धर्मांतरति होने वाले दलतियों हेतु अनुसूचति जात आरकषण प्रदान कयि जाने की सफिरशि की गई थी ।
- दलति ईसाइयों और मुसलमानों को न केवल अपने धर्म के उच्च जात के सदस्यों से बल्क वियापक हदि-वरचस्व वाले समाज से भी भेदभाव का सामना करना पडता है ।
- ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाते वाले दलतियों को SC श्रेणी से बाहर रखना समानता की संवैधानकि गारंटी का उल्लंघन है तथइन धर्मों के मूल सदिधांतों के खलिाफ है, जो जातगित भेदभाव को अस्वीकार करते हैं ।
- ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरति होने वाले दलतियों को SC का दरजा देने से इनकार करने के कारण वे सामाजकि-आर्थकि और शैकषकि रूप से पीछे रह गए हैं तथा उन्हें शकिषा एवं रोजगार के अवसरों में आरकषण तक पहुँच से वंचति कयि गया है (जैसा कि [अनुच्छेद 16](#) के तहत प्रदान कयि गया है) ।

वर्ष 1950 के संवधान आदेश में कौन शामिल हैं?

- अधनियम पारति होने पर [1950 का संवधान \(अनुसूचति जात\) आदेश](#) शुरू में केवल हदिओं को अनुसूचति जात के रूप में मान्यता देने के लयि

- प्रदान किया गया था, ताक़ाअसपृश्यता के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमता को दूर किया जा सके।
- इस आदेश में वर्ष 1956 में संशोधन किया गया था ताक़ासखि धर्म अपनाने वाले दलितों को इसमें शामिल किया जा सके तथा वर्ष 1990 में एक बार फ़रि बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को इसमें शामिल करने हेतु संशोधन किया गया।
 - दोनों संशोधनों को वर्ष 1955 में काका कालेलकर आयोग और वर्ष 1983 में क्रमशः अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल (HPP) की रिपोर्टों से सहायता मिली थी।
 - 1950 का आदेश (1956 और 1990 में संशोधन के बाद) यह अनविरय करता है किकोई भी व्यक्तियों हद्वि, सखि या बौद्ध नहीं है, उसे अनुसूचित जातिका दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

दलति ईसाइयों और मुसलमानों को बाहर रखने का कारण:

- अनुसूचित जातकी जनसंख्या में वृद्धिसे बचने हेतु: भारत के महापंजीयक (RGI) कार्यालय ने सरकार को आगाह किया था किकानुसूचित जातिका दर्जा असपृश्यता की प्रथा (जो किकहिद्वि और सखि समुदायों में प्रचलति थी) से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित समुदायों के लिये है।
 - यह भी उल्लेख किया गया किकिस तरह के कदम से देश भर में अनुसूचित जातकी आबादी में काफी वृद्धि होगी।
- वविधि नृजातीय समूह जनिहोंने धर्मांतरण कयि: RGI के अनुसार, वर्ष 2001 में इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले दलति कसिी एक नृजातीय समूह से नहीं बल्कि अलग-अलग जातगित समूहों से संबंधित हैं।
 - इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचित जात(SC) की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योकिकिस सूची में शामिल कयि जाने हेतु एकल जातीय समूह से संबंधित होने की आवश्यकता होती है।
- असपृश्यता अन्य धर्मों में प्रचलति नहीं: RGI ने आगे कहा है किकिचूँकि "असपृश्यता" की प्रथा हद्वि धर्म और इसकी शाखाओं की एक वशिषता थी ऐसे में दलति मुसलमानों और दलति ईसाइयों को SCs के रूप में सूचीबद्ध करने कयि जाने की अनुमतिको "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत समझा जा सकता है" और यह माना जा सकता है किकिभारत ईसाइयों तथा मुसलमानों पर "अपनी जातविवस्था को थोपने" की कोशिश कर रहा है।
 - वर्ष 2001 के नोट में यह भी कहा गया है किकदलति मूल के ईसाई और मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन के माध्यम से अपनी जातगित पहचान खो दी थी और उनके नए धार्मिक समुदाय में असपृश्यता की प्रथा प्रचलति नहीं है।

भारत का महापंजीयक:

- भारत का महापंजीयक की स्थापना वर्ष 1961 में गृह मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- यह [भारत की जनगणना](#) और [भारतीय भाषाई सर्वेक्षण](#) सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन एवं वशि्लेषण करता है।
- महापंजीयक का पद सामान्यतः एक सविलि सेवक के पास होता है जो संयुक्त सचिव का पद धारण करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. वर्ष 2001 में आर.जी.आई. ने कहा किकदलति जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, वे एक भी जातीय समूह नहीं हैं क्योकिकिे वभिनिन जातिसमूहों से संबंधित हैं। इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचित जात(SC) की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, जसिमें शामिल करने हेतु एकल जातीय समूह की आवश्यकता होती है। (मुख्य परीक्षा, 2014)

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जातआयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रयान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2018)

स्रोत: द हद्वि